



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062021-227415  
CG-DL-E-08062021-227415

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2017]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943

No. 2017]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2021/JYAISTHA 18, 1943

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

**का.आ. 2176(अ).**—अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या का0 आ0 1114 (अ), तारीख 12 मार्च, 2018 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा महानदी जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन अंतर्राज्यीय महानदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण को अपनी रिपोर्ट और यथाअपेक्षित विनिश्चय को तारीख 11 मार्च 2021 को या उससे पूर्व देना अपेक्षित था;

और अपरिहार्य कारणों से उक्त अधिकरण अपनी रिपोर्ट तीन वर्ष की उक्त अवधि में प्रस्तुत नहीं कर सका था;

और, उक्त अधिकरण ने केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम 1956 (1956 का 33) की धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानदी जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और

विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को दो वर्षों के लिए तारीख 11 मार्च, 2023 तक अथवा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाती है।

[फा.सं. 70012/1/2021-बी0एम0]

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF JAL SHAKTI**

**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd June, 2021

**S.O. 2176 (E).**—Whereas, the Mahanadi Water Disputes Tribunal (hereafter in this notification referred to as the said Tribunal) was constituted on the 12<sup>th</sup> March, 2018 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation number S.O. 1114(E), dated the 12<sup>th</sup> March, 2018, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereafter in this notification referred to as the said Act), for the adjudication of the water disputes regarding inter-State river Mahanadi and river valley thereof;

And, whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision as required under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, i.e., on or before the 11<sup>th</sup> March, 2021;

And, whereas, due to unavoidable reasons, the said Tribunal could not submit its report within the said period of three years;

And, whereas, the said Tribunal has requested the Central Government to extend the said period for submission of report and decision thereon;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (2) of section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by the Mahanadi Water Disputes Tribunal for a period of two years upto 11<sup>th</sup> March, 2023 or till the submission of report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act, whichever is earlier.

[F.No. N-70012/1/2021-BM]

SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.